रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 159] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 31, 2001/चैत्र 10, 1923
No. 159] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 31, 2001/CHAITRA 10, 1923

CENTRAL LIBRARY GOVT. OF INDIA

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय
(विधायी विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2001

सा.का.नि. 236(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

"सं.आ. 185"

संविधान (राजस्व वितरण) संख्यांक 3 आदेश, 2001

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 275 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात् :—

1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम, (राजस्व वितरण) संख्यांक 3 आदेश, 2001 है।

2. साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) इस आदेश के निर्वचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह किसी केन्द्रीय अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है।

3. (1) अनुच्छेद 275 के खंड (1) के उपबंधों के अनुसार 1 अप्रैल, 2000 को प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष में, नीचे विनिर्दिष्ट राज्यों में से प्रत्येक के सहायता अनुदान के रूप में उनके सामने विनिर्दिष्ट राशियां, जो राज्यों में तूफान, सूखा, भूकंप, आग, बाढ़ और ओलावृष्टि से पीड़ितों के लिए प्राकृतिक विपत्ति के संबंध में राहत देने के लिए राज्य विपत्ति राहत निधियों हेतु केन्द्रीय सरकार के अभिदाय के रूप में हैं, भारत की संचित निधि पर भारित होंगी :—

राज्य	रु. लाख में
(1)	(2)
1. आंध्र प्रदेश	14854.00
2. अरूणाचल प्रदेश	902.00
3 असम	7612.00
4. बिहार	5022.00
5. छत्तीसगढ़	2060.00
6. गोवा	46.50
7. गुजरात	13113.51
8. हरियाणा	6098.00
9. हिमाचल प्रदेश	3261.00
10. जम्मू-कश्मीर	2618.00
11. झारखंड	4252.00
12. कर्नाटक	5593.00
13. केरल	1734.39
14. मध्य प्रदेश	4698.00
15. महाराष्ट्र	11790.00
16. मणिपुर	156.00
17. मेघालय	295.00
18. मिजोरम	111.50
19. नागालैंड	53.08
20. उड़ीसा	10365.25
21. पंजाब	9204.00
22. राजस्थान	19600.25
23. सिक्किम	294.66
24. तमिलनाडु	7698.00
25. त्रिपुरा	140.83

(1)	(2)
26. उत्तर प्रदेश	3208.44
27. उत्तरांचल	709.91
28. पश्चिमी बंगाल	7583.00

परंतु यह कि ऊपर विनिर्दिष्ट राशियां ऊपर विनिर्दिष्ट प्राकृतिक विपत्तियों के संबंध में राहत देने के लिए उपायों पर 1 अप्रैल, 2000 को प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष में व्यय की जाएंगी।

परंतु यह और कि राहत उपायों पर वास्तविक व्यय, जैसा कि उस वर्ष के लेखाओं में प्रकट किया गया है, ऊपर विनिर्दिष्ट राशियों से कम है तो अतिशेष, राज्य के विपत्ति राहत निधि के भाग के रूप में राज्य सरकार को उपलब्ध बना रहेगा।

(2) 1 अप्रैल, 2000 को प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष में किसी राज्य को उप-पैरा (1) के अधीन संदेय राशियों की कोई राशि संविधान (राजस्व वितरण) आदेश, 2000 के पैरा 3 के उप पैरा (1) के अनुसरण में वित्तीय वर्ष में उस राज्य को संदेय राशि या राशियों के अतिरिक्त होंगी।

के. आर. नारायणन,
राष्ट्रपति

[फ. सं. 19(3)/2001-वि. I]
सुभाष सी. जैन, सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2001

G.S.R. 236 (E).—The following Order made by the President is published for general information :

"C.O. 185"

THE CONSTITUTION (DISTRIBUTION OF REVENUES) NO. 3 ORDER, 2001

In exercise of the powers conferred by article 275 of the Constitution, the President, after having considered the recommendations of the Finance Commission, hereby makes the following Order, namely :—

1. This Order may be called the Constitution (Distribution of Revenues) No. 3 Order, 2001.

2. The General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), shall apply for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of a Central Act.

3. (1) In accordance with the provisions of clause (1) of article 275, there shall be charged on the Consolidated Fund of India, in the financial year commencing on the 1st day of April, 2000, as grants-in-aid of the revenues of each of the States specified below, the sums specified against it, as representing the contribution of the Central Government towards State Calamity Relief Funds for affording relief to the victims of cyclone, drought, earthquake, fire, flood and hailstorm in the States:—

State		(Rs. in lakhs)
	(1)	(2)
1	Andhra Pradesh	14854.00
2.	Arunachal Pradesh	902.00
3.	Assam	7612.00
4.	Bihar	5022.00
5	Chhattisgarh	2060.00
6	Goa	46.50
7.	Gujarat	13113.51
8	Haryana	6098.00
9	Himachal Pradesh	3261.00
10.	Jammu and Kashmir	2618.00
11.	Jharkhand	4252 00
12.	Karnataka	5593.00
13	Kerala	1734.39
14.	Madhya Pradesh	4698.00
15.	Maharashtra	11790.00
16.	Manipur	156.00
17	Meghalaya	295.00
18.	Mizoram	111.50
19	Nagaland	53.08
20	Orissa	10365.25
21.	Punjab	9204.00
22.	Rajasthan	19600.25
23.	Sikkim	294.66
24.	Tamil Nadu	7698.00
25.	Tripura	140.83
26.	Uttar Pradesh	3208.44
27	Uttaranchal	709.91
28.	West Bengal	7583 00;

Provided that the sums specified above shall be expended in the financial year commencing on the 1st day of April, 2000 on measures for affording relief in connection with natural calamities specified above;

Provided further that if the actual expenditure on relief measures as revealed in the accounts of that year, is lower than the sums specificed above, the balance shall remain available to the State Government as part of the Calamity Relief Fund of the State.

(2) any sum or sums payable under sub-paragraph (1) to any State, in the financial year commencing on the 1st day of April, 2000 shall be in addition to the sum or sums payable to that State in the financial year in pursuance of sub-paragraph (1) of pragraph 3 of the Constitution (Distribution of Revenues) Order, 2000.

K R. NARAYANAN,
President

[F. NO. 19(3)/2001-LI]
SUBHASH C. JAIN,